

## राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

### प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान, सतत् वकस लक्ष्य (SDG) ।

### मेन्स के लयः

पंचायती राज संस्थान (PRI), 15वाँ वतित आयोग, ई-पंचायत पर मशिन मोड प्रोजेक्ट, ई-गवर्नेंस, सतत् वकस लक्ष्य (SDG) ।

## चर्चा में क्यों?

आर्थक मामलों की मंत्रमंडलीय समति ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान' (RGSA) की संशोधति [केंद्र प्रायोजति योजना](#) को जारी रखने की मंजूरी दी है ।

- यह योजना अब 15वें वतित आयोग की रपौर्ट की अवधि के साथ समाप्त होगी ।
- इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की शासन क्षमताओं को वकसति करना है ।

## राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान (RGSA) क्या है?

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को पहली बार वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रमंडल द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लयि मंजूरी दी गई थी ।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** पंचायती राज मंत्रालय ।
- **घटक:** मुख्य केंद्रीय घटकों में पंचायतों को प्रोत्साहन देना एवं केंद्रीय स्तर पर अन्य गतविधियों सहति ई-पंचायत पर मशिन मोड परियोजना को लागू करना है ।
  - राज्य घटकों में मुख्य रूप से क्षमता नरिमाण और प्रशक्तिषण (CB&T) गतविधियों, CB&T के लयि संस्थागत तंत्र के साथ-साथ सीमति स्तर पर अन्य गतविधियों शामिल हैं ।
- **उद्देश्य:** इसमें सतत् वकस लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के लयि पंचायती राज संस्थानों (PRIs) की शासन क्षमताओं को वकसति करने की परकिल्पना की गई है ।
  - SDGs के प्रमुख सदिधांत, यानी कसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबसे पहले एवं सार्वभौमकि कवरेज तक पहुँचना, लैंगकि समानता के साथ-साथ प्रशक्तिषण, प्रशक्तिषण मॉड्यूल और सामगरी सहति सभी क्षमता नरिमाण हस्तक्षेपों को डिजाइन में शामिल कया जाएगा ।
  - मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्त्व के वषियों को प्राथमकिता दी जाएगी, अर्थात्:
    - गाँवों में गरीबी से मुक्ति एवं आजीविका में बढ़ोतरी
    - स्वस्थ गाँव
    - बच्चों के अनुकूल गाँव
    - जल पर्याप्त गाँव
    - स्वच्छ और हरा-भरा गाँव
    - गाँव में आत्मनरिभर बुनयादी ढाँचा
    - सामाजकि रूप से सुरक्षति गाँव
    - सुशासन वाला गाँव
    - ग्राम वकस में बढ़ोतरी ।
- **फंडिंग पैटर्न:** संशोधति RGSA में केंद्र एवं राज्य के घटक शामिल होंगे । योजना के केंद्रीय घटकों को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वतितपोषति कया जाएगा ।
  - राज्य घटकों के लयि वतितपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में होगा, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य का हसिसा 90:10 होगा ।
  - साथ ही अन्य केंद्रशासति प्रदेशों के लयि केंद्रीय हसिसा 100% होगा ।
- **वज़िन:** यह "सबका साथ, सबका गाँव, सबका वकस" (Sabka Sath, Sabka Gaon, Sabka Vikas) हासलि करने की दशिा में एक प्रयास है ।

■ महत्त्व:

- सामाजिक-आर्थिक न्याय: चूँकि पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है और वे ज़मीनी स्तर के सबसे करीब संस्थान हैं, पंचायतों को मज़बूत करने से सामाजिक न्याय व समुदाय के आर्थिक विकास के साथ-साथ समानता तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
- बेहतर लोक सेवा उपलब्ध कराना: पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ई-गवर्नेंस के बढ़ते उपयोग से बेहतर सेवा वितरण और पारदर्शिता हासिल करने में मदद मिलेगी।
- PIR का विकास: यह पर्याप्त मानव संसाधन और बुनियादी ढाँचे के साथ राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर PIR के क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत ढाँचे की स्थापना करेगा।

■ लाभार्थी: RGSA की स्वीकृत योजना से 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को मदद मिलेगी।

- देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे।

■ वसितार: इस योजना का वसितार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक है तथा भाग IX में शामिल क्षेत्रों के आलावा ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएँ भी शामिल होंगी, जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न: (पीवाईक्यू):

प्रश्न.. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य नमिनलखिति में से कसि सुनश्चिति करना है? (2015)

1. विकास में लोगों की भागीदारी।
2. राजनीतिक जवाबदेही।
3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
4. वित्त जुटाना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मौलिक उद्देश्य विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
- पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना स्वतः ही राजनीतिक उत्तरदायित्व की ओर नहीं ले जाती है।
- वित्त जुटाना पंचायती राज का मूल उद्देश्य नहीं है, हालाँकि यह ज़मीनी स्तर पर सरकार को वित्त और संसाधनों को हस्तांतरित करने में सहायक है।

?????: ?????? ??????????